3.19 लाख करोड़ का निवेश हुआ है सरकारी बैंकों में पिछले पांच साल में। इसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश सरकार ने किया है, जबकि 66,000 करोड़ रुपये से अधिक इन बैंकों ने खुद जुटाए हैं।

कांग्रेस में अपनी नई भूमिका का संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्यों के नेताओं से मेल-मुलाकात का दौर किया शुरू
- अध्यक्ष पद छोड़ने की स्थिति में भी कम नहीं होगी भूमिका, कांग्रेस के तमाम नेता अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने का बना रहे दबाव

राहुल गांधी जागरण आर्काइव

कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी ने नेताओं से मेल-मुलाकातों का दौर शुरू कर अपनी सियासी सक्रियता जारी रखने का साफ संकेत दे दिया है। तमाम राज्यों के पार्टी नेताओं से बातचीत का सिलसिला शुरू कर राहुल ने पार्टीजनों को यह संदेश देना शुरू कर दिया है कि अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई में उनकी सक्रिय भूमिका कम नहीं होगी।

लोकसभा चुनाव की हार के मद्देनजर एक महीने पहले कार्यसमिति में इस्तीफे की पेशकश करने के बाद राहुल ने पार्टी नेताओं से मिलना-जुलना लगभग बंद कर दिया था। मगर बीते तीन चार दिनों से बतौर अध्यक्ष राज्यों के नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू किया है। दो दिन पहले छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई थी। केरल के नेता भी इस दौरान उनसे मिले। अब 27 जून को हरियाणा तो 28 जून को दिल्ली के पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है। हरियाणा और दिल्ली के पार्टी नेताओं से राहुल की मुलाकात अहम है क्योंकि इन दोनों सूबों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। साथ ही हरियाणा में पार्टी के अंदर जबरदस्त कलह चल रही है।

लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के समक्ष खड़ी चुनौतियों के पहाड़ के बीच राहुल के इस्तीफे ने कांग्रेस के भीतर जबदस्त खलबली मचा रखी है। पार्टी की राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए कांग्रेस के तमाम नेता राहुल पर अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने का दबाव डाल रहे हैं। जबकि राहुल वरिष्ठ नेताओं को साफ कह चुके हैं कि पार्टी को नए अध्यक्ष का विकल्प जल्द से जल्द तलाश लेना चाहिए। मगर अब भी कांग्रेस नेताओं का बड़ा वर्ग सोनिया गांधी के जरिए राहुल पर फैसला बदलने के लिए दबाब बनाने से गुरेज नहीं कर रहा। इन नेताओं का तर्क है कि मौजूदा हालात में कांग्रेस के पास राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है और उनके अध्यक्ष पद छोड़ने से पार्टी की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में सूबे के नेताओं से मुलाकात कर राहुल पार्टी नेताओं के इस भय को दूर करने का भी संदेश देना चाहते हैं कि अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी कांग्रेस की जमीनी सियासत को दुरूस्त करने में उनकी भूमिका कम नहीं रहेगी।

बहरहाल राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इतर भावी भूमिका का संदेश भले दें मगर पार्टी के भीतर अब भी उन पर इस्तीफे की पेशकश वापस लेने का दबाव बना हुआ है। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चंद्र यादव की अगुआई में पार्टी की युवा इकाई बुधवार को राहुल गांधी के निवास तुगलक लेन के सामने इकठ्ठा होकर उनसे कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहने की खुली अपील करेगी। वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा कांग्रेस की इस पहल से साफ है कि पार्टी ने राहुल पर फैसला बदलने का दबाव डालने की अपनी मुहिम अभी छोड़ी नहीं हैं।

एस-400 खरीदने के फैसले में बदलाव नहीं करेगा भारत

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- अमेरिकी विदेश मंत्री पोंपियो की आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री से वार्ता
- ई कामर्स और डाटा लोकलाइजेशन नीति पर भारत के मन की थाह लेंगे पोंपियो

नई दिल्ली में मंगलवार को पालम हवाई अड्डे पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियों की अगवानी भारतीय अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंटकर की। इस मौके पर भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर भी मौजूद रहे। प्रेट्र

अमेरिका के बेहद दबाव के बावजूद भारत अपने पुराने रणनीतिक मित्र रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम एस-400 खरीदने के फैसले में कोई बदलाव नहीं करेगा। बुधवार को जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोंपियो की नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी तो उसमें इस बारे में साफ तौर पर बता दिया जाएगा। भारत का रूख यह है कि जिस कानून के तहत अमेरिका रूस से रक्षा सौदे पर पाबंदी की बात कर रहा है, उसी कानून के तहत उसे एस-400 खरीदने की छूट मिलने का प्रावधान है।

सत्ता में मोदी सरकार की वापसी के बाद अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो दोनों देशों के बीच काफी गहरे ताल्लुक की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कारोबारी क्षेत्र में कई तरह के नए विवाद सिर उठा रहे हैं। ऐसे में पोंपियो मंगलवार शाम को नई दिल्ली पहुचे हैं।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार किसी बड़े देश का विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आ रहा है। यह मोटे तौर पर आगे पांच वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच की साझेदारी का रोडमैप बनाने की तैयारी है। साथ ही दो दिन बाद ही ओसाका (जापान) में मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, पोंपियो की यात्रा उसकी भी नींव तैयार करेगी। हालांकि, दोनों देशों के बीच हर मुद्दे पर बात तो होगी लेकिन कोई समझौता या करार नहीं होगा।

हाल के दिनों में कई बार अमेरिका ने भारत की तरफ से रूस से एस-400 सिस्टम खरीदने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। इस बारे में विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि, रूस के साथ बेहद पुराने रिश्ते को हम नकार नहीं सकते। वैसे भी रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून में भारत को छूट मिलनी चाहिए। अमेरिका को मालूम है कि भारत किस तरह की रणनीतिक जरुरत के लिए इस सिस्टम को खरीद रहा है। इसी तरह से ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध का भी मुद्दा है जो सीधे तौर पर भारत के हितों को प्रभावित करता है। यह मुद्दा भी पोंपियो के साथ उठाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि प्रतिबंध की वजह से भारतीय तेल कंपनियों ने फिलहाल ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है लेकिन ईरान से भी बातचीत जारी है। हो सकता है कि भविष्य में ईरान से फिर से तेल की खरीद की जाए।

यह पूछे जाने पर कि क्या चीन की कंपनी हुवेई पर प्रतिबंध लगाने का अमेरिका दबाव माना जाएगा, इस बारे में सूत्रों का कहना है कि भारत 5जी तकनीकी को लेकर अपनी नीति स्वयं बना रहा है। डाटा सुरक्षा को लेकर वह अपने आतंरिक मुद्दों को देख कर फैसला करेगा। हुवेई की तरह ही अमेरिकी विदेश मंत्री डाटा लोकलाइजेशन और ई-कामर्स नीति पर भारत सरकार का मन थाहने की कोशिश करेंगे।

तनाव वाले मुद्दे

- रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम एस-400 की खरीद
- ईरान से तेल खरीदने पर लगी पाबंदी
- भारत सरकार की नई ई-कामर्स नीति
- डाटा लोकलाइजेशन पर नई नीति
- भारत के उच्च शिक्षित कामगारों पर लगातार पाबंदी लगाने की कोशिश
- अमेरिका की चाह, भारत भी चीनी कंपनी हुवेई पर लगाए प्रतिबंध
- आटोमोबाइल पर भारत घटाए सीमा शुल्क

गुजरात में राज्यसभा की दोनों सीटों पर अलग-अलग ही होंगे चुनाव

झटका ▶ सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका ठुकराई, चुनाव में दखल देने से किया इन्कार

चुनाव बाद याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की मांग वाली कांग्रेस की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है इसलिए अभी कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है।

अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गुजरात में राज्यसभा की दोनों सीटें खाली हो गई हैं। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दोनों सीटों पर पांच जुलाई को अलग-अलग चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की है। कांग्रेस ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव की मांग की थी।

मंगलवार को जस्टिस संजीव खन्ना और बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने गुजरात कांग्रेस के नेता परेश धनानी की याचिका खारिज करते हुए उक्त आदेश दिए। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में चुनाव याचिका दाखिल करने की विधायी व्यवस्था याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध है और याचिकाकर्ता चुनाव खत्म होने के बाद संबंधित हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है। जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को गलत और असंवैधानिक बताया तो पीठ ने याचिका पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा कि इस मामले में उनके किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि विधायी अधिकार है।

इससे पहले चुनाव आयोग ने भी याचिका पर सवाल उठाते हुए उसे रद करने की मांग की थी। आयोग ने कहा था कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और सामान्य तौर कोर्ट चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद दखल नहीं देता। आयोग ने याचिका के विरोध में दाखिल हलफनामे में कहा था कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने में कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। यह प्रक्रिया 1957 से अपनाई जा रही है।

इसलिए की थी एक साथ चुनाव की मांग : असल में गुजरात विधानसभा में भाजपा के 100 और कांग्रेस के 75 विधायक हैं, जबकि सात सीटें इस वक्त खाली हैं। अगर दोनों सीटों को भरने के लिए एक साथ चुनाव हुए और विधायकों ने सिर्फ एक बार में वोट दिया तो कांग्रेस के पास एक सीट जीतने का मौका होगा। अगर दोनों सीटों के लिए अलग-अलग वोटिंग हुई तो भाजपा दोनों सीटों को जीत सकती है क्योंकि विधानसभा में उसका बहुमत है। संख्या बल के हिसाब से गुजरात में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोट चाहिए। बता दें कि एक ही बैलेट पर चुनाव से उम्मीदवार एक ही वोट डाल पाएगा। इस स्थिति में कांग्रेस एक सीट आसानी से निकाल लेती। लेकिन चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, विधायक अलग-अलग वोट करेंगे। ऐसे में उन्हें दो बार वोट करने का मौका मिलेगा। इस तरह भाजपा के विधायक जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है वे दो बार वोट करके दोनों उम्मीदवारों को जितवा सकते हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा

गांधीनगर, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को गुजरात में पांच जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघाणी मौजूद थे। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सोमवार को दिल्ली में भाजपा की सदस्यता लेने के कुछ घंटों बाद उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था जिसके बाद जयशंकर सोमवार शाम अहमदाबाद पहुंचे। मोदी के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार में जयशंकर (64) विदेश सचिव थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है।

गुजरात भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और मेहसाणा निवासी जुगलजी ठाकोर ने राज्य की दूसरी राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। दरअसल, भाजपा नेता अमित शाह और स्मृति ईरानी के पिछले माह लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह दोनों सीटें खाली हुई थीं। नियमानुसार कोई मंत्री जो दोनों सदन का सदस्य नहीं है, उसका शपथ ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी ना किसी सदन के लिए चुना जाना जरूरी होता है।

संसद प्रश्नोत्तर

अब तक आइएस के 155 सदस्य और समर्थक गिरफ्तार : रेड्डी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन आइएस के 155 सदस्यों और उसके समर्थकों को अब तक देश में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के कुछ व्यक्तियों द्वारा इस आतंकी संगठन में शामिल होने की जानकारी केंद्रीय और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। यह जानकारी गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

जी किशन रेड्डी फाइल फोटो

पिछले तीन सालों में जम्मू-कश्मीर में मारे गए 700 से अधिक आतंकी : पिछले तीन सालों के दौरान जम्मू-कश्मीर में 733 आतंकी मारे गए। 2018 में 257, 2017 में 213 और 2016 में 150 आतंकी मारे गए। इस साल जनवरी से लेकर 16 जून तक की बात करें तो 113 आतंकी मारे गए हैं। तीन सालों के दौरान 112 आम नागरिकों को भी विभिन्न आतंकी घटनाओं में जान गंवानी पड़ी है। यह जानकारी गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में दी।

देश में नक्सल वारदातों में आई कमी : 2009-13 के मुकाबले पांच सालों के दौरान देश में होने वाली नक्सल वारदातों में जहां 43.4 फीसद की कमी आई, वहीं इसके चलते होने वाली मौतों में 60.4 फीसद की कमी आई है। 2009-2013 के बीच नक्सली हिंसा के 8,782 मामले दर्ज किए गए जबकि 2014-18 के बीच यह घटकर 4,969 रह गए। नक्सल हिंसा के चलते सुरक्षा बलों सहित 3,326 लोगों को जान गंवानी पड़ी जबकि 2014-18 के बीच यह संख्या घटकर 1,321 हो गई। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

अर्धसैनिक बलों में 84,000 पद रिक्त : अर्धसैनिक बलों में स्वीकृत 9,99,795 पदों के मुकाबले 84,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें भरने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और मृत्यु के चलते यह पद रिक्त हुए हैं। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रत्येक साल 10 फीसद पद रिक्त होते हैं और इन्हें भरने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

चक्रवात फणि ने ली 64 लोगों की जान : चक्रवात फणि की चपेट में आकर 64 लोगों की मौत हुई और 1,48,663 हेक्टेअर फसल बर्बाद हुई जबकि 5.56 लाख घर और झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा। यह जानकारी मंगलवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में दी। चक्रवात फणि से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए थे, लेकिन आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

देसी नस्ल की गाय के संरक्षण के लिए सरकार ने उठाए कदम : गिरिराज

नई दिल्ली, प्रेट्र : गोकुल मिशन के तहत सरकार ने देसी नस्ल की गाय के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। अगले पांच वर्षों में स्थानीय नस्लें भी विदेशी जैसी होंगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान रवींद्र श्याम शुक्ल (रवि किशन) के सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। गिरिराज ने कहा कि गायों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पशुपालन खेती से ज्यादा लाभकारी है। उन्होंने कहा कि वंश जांच कार्यक्रम और देसी नस्ल के उच्च जेनेटिक मेरिट सांड की उत्पत्ति के लिए नस्ल चयन कार्यक्रम, भ्रूण हस्तांतरण तकनीक और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब शुरू किए जा रहे हैं। बछड़े की जगह बछिया के जन्म के लिए भी सुविधा विकसित की जा रही है।

सरकार ने फसल बीमा पर राज्यों से राय मांगी

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर इस बात पर राय मांगी है कि क्या किसानों के लिए फसल बीमा को स्वैच्छिक/वैकल्पिक बनाया जा सकता है। वर्तमान में यह योजना प्रकृति में अनिवार्य है। कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि कुछ राज्य सरकारों और किसान संघों ने कृषि मंत्रालय से योजना को स्वैच्छिक बनाने की मांग की थी। लिखित उत्तर में सरकार ने कहा है कि इस योजना को उन किसानों के लिए अनिवार्य किया गया है जिन्होंने कर्ज लिया है और जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है उनके लिए स्वैच्छिक है।

घोटालेबाज मेहुल चोकसी को घेरने की होगी हर तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चोकसी के खिलाफ भारतीय एजेंसियों की घेराबंदी ढीली नहीं पड़ेगी। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउनी ने चोकसी के भारत लौटने की राह आसान करने के संकेत दिए हैं लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक तरफ जहां कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें जारी रखी जाएंगी वहीं एंटीगुआ के स्थानीय कानून के तहत चोकसी के प्रत्यर्पण के मामले में भी लगातार कोशिश करनी होगी। एक आशंका यह भी है कि नागरिकता समाप्त होने के बाद चोकसी के वकील मामले को दूसरी तरह से लटकाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में स्थानीय कानून की जरूरतों को पूरा करने में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को लगातार सतर्क रहना होगा।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि चोकसी को भारत लाने की राह में उसकी एंटीगुआ की नागरिकता एक बड़ी अड़चन थी लेकिन ऐसा नहीं है कि नागरिकता रद्द होने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसी संभावना है कि चोकसी की तरफ से स्थानीय मानवाधिकार कानून की आड़ में प्रत्यर्पण को और लटकाया जाए। भारतीय एजेंसियों को इसके लिए भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार रहना होगा। सनद रहे कि भारत कैरिबियाई देश एंटीगुआ व बारबुडा पर लगातार कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना के रिश्तेदारों से पूछा, क्या लौटने की गारंटी देंगे?

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना के दो रिश्तेदारों से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि क्या वे उसके चिकित्सकीय आधार पर विदेश जाने की अनुमति के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये जमा कराकर गारंटी देंगे? इसके लिए उन्हें बुधवार तक का समय दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और बीआर गवई ने ईडी की आपत्ति पर संज्ञान लेते हुए यह सवाल किया। राजीव को दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्लड कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

भारतीय परंपराओं के आकर्षण का केंद्र बनीं सांसद नुसरत जहां

नई दिल्ली, एएनआइ/प्रेट्र/आइएएनएस : नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस सांसदों नुसरत जहां रूही और मिमी चक्रवर्ती ने मंगलवार को लोकसभा में अपने पद की शपथ ली। बसीरहाट के सांसद नुसरत और जाधवपुर की सांसद मिमी ने पिछली बार संसद में पहने पश्चिमी परिधान से उठे विवाद के बाद संसदीय मर्यादा के अनुरूप इस बार क्रमशः साड़ी और सूट पहना। नवविवाहिता नुसरत ने खूबसूरत गुलाबी किनारी वाली सफेद साड़ी पहनी थी। माथे पर सिंदूर और बिंदी दमक रही थी। हाथों में मेहंदी और शादी का लाल चूड़ा था। वहीं उनकी मित्र और सांसद मिमी ने सफेद रंग का सूट पहना। बांग्ला फिल्म जगत से राजनीति में आई इन दोनों सांसदों ने विगत 17 व 18 जून को शपथ नहीं ली थी, क्योंकि पिछले दिनों नुसरत जहां ने तुर्की के बोडरम शहर में कोलकाता के कारोबारी निखिल जैन से शादी कर ली और उनकी मित्र मिमी इस भव्य शादी समारोह में शामिल होने गई थीं।

जैसे ही मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई दोनों तृणमूल सांसदों ने बांग्ला में शपथ ली और इसे वंदे मातरम, जय हिंद और जय बांग्ला जैसे जयघोष के साथ खत्म किया। इसके बाद दोनों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास जाकर उनके पैर छुए। संसद में प्रवेश करते हुए दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज में संसद भवन की सीढ़ियों को छूकर संसद के प्रति सम्मान जताया। दोनों युवा सांसद संसद भवन से बाहर आते समय उस समय आपा खो बैठीं जब उन्हें मीडिया कर्मियों की ओर से की गई धक्का-मुक्की का शिकार होना पड़ा।

नई दिल्ली में मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद संसद भवन से प्रस्थान करतीं तृणमूल कांग्रेस सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां तथा मिमी चक्रवर्ती। प्रेट्र

युद्ध-नीति साझेदारी

सुखोई और आइएल-78 विमान फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास करने के लिए हुए रवान,।

फ्रांस के साथ छठा गरुड़ अभ्यास एक जुलाई से

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वायुसेना के सुखोई-30 विमान फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास में होंगे शामिल

भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट फ्रांस के लड़ाकू राफेल विमान के साथ गरुड़-शृंखला हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए मंगलवार को फ्रांस रवाना हो गए। दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच होने जा रहे सबसे बड़े हवाई युद्धाभ्यास में, भारतीय दल को राफेल विमानों के साथ उड़ान भरने का मौका मिलेगा। राफेल इस साल सितंबर से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में शामिल होने जा रहा है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के आपसी सैन्य संबंधों को मजबूती देने के लिए यह व्यापक वायुसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। गरुड़ अभ्यास के तहत वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के बेड़े के साथ ही हवा में ईंधन भरने वाले विमान आइएल-78 को भी फ्रांस भेजा गया है। वायुसेना की भागीदारी में सुखोई -30 एमकेआइ, आइएल-78 टैंकर एयरक्राफ्ट और इलयुशिन आइएल-76 अवाक्स एयरबोन शामिल है।

दोनों रणनीतिक सहयोगियों के बीच इस अभ्यास का बड़ा महत्व है। इस युद्धाभ्यास में 120 से ज्यादा वायुसेना अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने जा रहा यह अभ्यास दो हफ्ते तक चलेगा। फ्रांस का राफेल फाइटर जेट के साथ भारत का सुखोई-30 फाइटर आकर्षण का केंद्र होगा। इस अभ्यास के लिए वायुसेना के सी-17- ग्लोबमास्टर विमान लॉजिस्टिक्स समर्थन देंगे।

भारतीय वायुसेना ने यहां बताया कि फ्रांसीसी वायुसेना के साथ वॉर गेम एक फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया है। इसके तहत वायुसैनिकों के दो समूहों ने मंगलवार को बरेली और आगरा से उड़ान भरी है। बरेली स्थित 24 स्क्वाड्रन 'हॉक्स' से भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। यहां वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि इस अभ्यास से दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और एक दूसरे की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और रणनीति को समझने का मौका मिलेगा। इस साझा युद्धाभ्यास से दोनों वायुसेनाओं के बीच पेशेवर आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय माहौल में युद्ध संचालन का अनुभव मिलेगा।

गौरतलब है कि युद्ध-नीति साझीदारी पर भारत और फ्रांस के बीच जनवरी 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2003 से गरुड़ युद्धाभ्यास कभी भारत में तो कभी फ्रांस में आयोजित हो रहा है। पहला गरुड़ फरवरी 2003 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया था। तब से विभिन्न गरुड़ अभ्यास फ्रांस और भारत में आयोजित किए गए हैं। पांचवा इंडो-फ्रांस गरुड़ अभ्यास 2004 में वायुसेना के जोधपुर स्थित स्टेशन पर आयोजित किया गया था।

इससे पहले भारत और फ्रांस ने हाल ही में अरब सागर में वरुणा सीरीज के तहत नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था, जिसमें भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों ने फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल-एम के साथ भाग लिया था। भारत और फ्रांस रणनीतिक साझीदार हैं और पिछले कई वर्षों में अपने रणनीतिक सहयोग को बढ़ा रहे हैं। भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत अपनी नौसेना के लिए स्कॉर्पीन के रूप में फ्रांसीसी पनडुब्बियों का विकल्प भी चुना है। पिछले कई वर्षों से परस्पर सहयोग में इजाफा कर रहे भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच वर्ष 2016 में 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ है। पहले राफेल विमान को इसी साल सितंबर में भारत आना है।

इस साल दो लाख भारतीय करेंगे हज यात्रा : नकवी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को बताया कि आजादी के बाद पहली बार रिकॉर्ड दो लाख भारतीय इस साल हज यात्रा करेंगे। इनमें 48 फीसद से ज्यादा महिलाएं हैं।

नकवी ने कहा, इस साल 2,340 से ज्यादा महिलाएं बिना मेहरम (पुरुष सहयात्री) हज यात्रा करेंगी, जबकि पिछले साल ऐसी महिलाओं की संख्या 1,180 थी। उन्होंने बताया कि पहली बार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के सभी आवेदक हज यात्रा पर जाएंगे क्योंकि हज कोटा बढ़ने की वजह से उनकी प्रतीक्षा सूची खत्म कर दी गई है। देशभर में 21 स्थानों और 500 से ज्यादा उड़ानों के जरिये हज यात्री बिना किसी सब्सिडी के प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 1.4 लाख हज यात्री भारतीय हज समिति के जरिये और 60 हजार यात्री विभिन्न हज समूह आयोजकों के जरिये हज यात्रा पर जाएंगे। हज यात्रियों के लिए मक्का में 16 और मदीना में तीन स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा मक्का में तीन और मदीना में एक अस्पताल भी स्थापित किया गया है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी